NEXT IAS

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का इतिहास

सिविल सेवा परीक्षा 2025

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का इतिहास

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024

विषयसूची

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का इतिहास

अध्याय 1

नेहरू युग (Nehruvian Era)..... 1

1.1 भारत का एकीकरण (Integration of India)..... 1

भारतीय राज्यों का वर्गीकरण (Classification of Indian States)..... 1

रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States)..... 2

विभाजन और उसके तात्कालिक परिणाम (Partition and its Aftermath)..... 8

राज्यों का भाषायी पुनर्गठन (Linguistic Reorganization of States)..... 9

भारत में आदिवासियों का एकीकरण (Integration of Tribals in India)..... 12

राजभाषा का मुद्दा (Issue of Official Language)..... 14

हिंदू संहिता/कोड विधेयक (Hindu Code Bill)..... 16

1.2 राजनीतिक विकास (Political Developments)..... 16

संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy)..... 16

एकल पार्टी के प्रभुत्व वाली व्यवस्था (One Party Dominated System)..... 17

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन (Decline of Indian National Congress)..... 17

1.3 विदेश नीति (Foreign Policy)..... 20

बांडुंग सम्मेलन (Bandung Conference), 1955..... 20

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Alignment Movement-NAM) 21

पंचशील समझौता (The Panchsheel Agreement)..... 22

1.4 भारत-चीन संबंध (India-China Relations)..... 23

तिब्बती संकट (Tibetan Crisis)..... 23

1962 का युद्ध (1962 War)..... 24

1.5 नेहरू युग का विश्लेषण (Analysis of Nehruvian Era).... 25

उपलब्धियाँ (Achievements)..... 25

कमियाँ (Shortcomings)..... 25

1.6 निष्कर्ष (Conclusion)..... 26

अध्याय 2

लाल बहादुर शास्त्री युग (Lal Bahadur Shastri Era)..... 27

2.1 परिचय (Introduction)..... 27

चुनौतियाँ (Challenges)..... 27

प्रतिक्रिया (Response)..... 27

2.2 राजनीतिक विकास (Political Developments)..... 27

कामराज योजना (Kamaraj Plan)..... 27

क्षेत्रीय दलों का उदय (Rise of Regional Parties)..... 28

2.3 ताशकंद समझौता (Tashkent Agreement)..... 29

भारत-पाक युद्ध (Indo-Pak War) 1965..... 29

ताशकंद घोषणा (Tashkent Declaration)..... 30

2.4 श्वेत क्रांति (White Revolution)..... 30

पृष्ठभूमि (Background)..... 30

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board)..... 32

ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood)..... 32

आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)..... 33

2.5 हरित क्रांति (Green Revolution)..... 33

अमेरिका से खतरा (Threat from the USA)..... 34

आत्मनिर्भरता की ओर (Towards Self-Reliance)..... 34

आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)..... 34

निष्कर्ष (Conclusion)..... 35

2.6 भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)..... 35

उपलब्धियाँ (Achievements)..... 35

चुनौतियाँ (Challenges)..... 36

संभाव्यता (Prospects)..... 36

2.7 लाल बहादुर शास्त्री काल: आलोचनात्मक विश्लेषण (Lal Bahadur Shastri Years : Critical Analysis)..... 36

उपलब्धियाँ (Achievements)..... 36

आलोचना (Criticism)..... 36

निष्कर्ष (Conclusion)..... 36

अध्याय 3

इंदिरा गाँधी युग (Indira Gandhi Era)..... 37

3.1 परिचय (Introduction)..... 37

इंदिरा गाँधी के लिए चुनौतियाँ (Challenges for Indira Gandhi)..... 37

3.2 राजनीतिक विकास (Political Development)..... 38

कांग्रेस में फूट (Split in Congress)..... 38

एकल दल से बहुदलीय प्रणाली (Single Party to Multi-party System)..... 39

गठबंधन सरकारों का युग (Era of Coalition Government)..... 39

दल-बदल की राजनीति (Politics of Defection)..... 40

जे.पी. नारायण और संपूर्ण क्रांति (JP Narayan and Total Revolution)..... 40

जनता सरकार: केंद्र में गठबंधन (Janata Government: Coalition at Centre) 41
गठबंधन राजनीति का विश्लेषण (Analysis of Coalition Politics)..... 41
3.3 आर्थिक विकास (Economic Development) 41
पीएल-480 कार्यक्रम (PL-480 Program)..... 41
राष्ट्रीयकरण: बैंक और साधारण बीमा (Nationalization: Banks and General Insurance) 42
सार्वजनिक वितरण प्रणाली [Public Distribution System (PDS)] 43
प्रिवी पर्स (शाही भत्ता) की समाप्ति (Abolition of Privy Purse) 43
गरीबी हटाओ (Garibi Hatao) 44
3.4 अन्य प्रमुख घटनाक्रम (Other Major Developments)..... 44
नक्सलवादी (The Naxalites)..... 44
3.5 बांग्लादेशी शरणार्थी संकट (Bangladeshi Refugee Crisis)..... 47
3.6 भारत-पाक युद्ध, 1971 (Indo-Pak War: 1971)..... 48
युद्ध की रणनीति (Strategy of War) 48
शिमला समझौता, 1972 (Simla Agreement) 49
भारत-सोवियत शांति संधि (Indo-Soviet Treaty of Peace) 50
3.7 जे.पी. आंदोलन (JP Movement)..... 50
3.8 राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)..... 51
घटनाएँ, जिनके कारण आपातकाल लगा (Events that led to the Emergency) 51
आपातकाल का घटनाक्रम (Course of Emergency)..... 52
न्यायपालिका के साथ संघर्ष (Tussle with Judiciary)... 52
जबरन या बलपूर्वक नसबंदी (Forced Sterilization)..... 52
जेल भरो आंदोलन (Jail Bharo Andolan) 53
राज नारायण प्रकरण (Raj Narain Case) 53
3.9 आपातकाल का विश्लेषण (Analysis of Emergency) 54

अध्याय 4

जनता सरकार (Janta Government)..... 55
4.1 परिचय (Introduction)..... 55
4.2 क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों का उदय (Rise of Regional Parties and Coalition Government) 55
44वाँ संवैधानिक संशोधन (44th Constitutional Amendment) 56
शाह आयोग की रिपोर्ट (Shah Commission Report) 57
काम के बदले अनाज कार्यक्रम (Food for Work Programme) 57
4.3 जनता सरकार का विश्लेषण (Analysis of Janata Government)..... 58
उपलब्धियाँ (Achievements) 58
विफलताएँ (Failures)..... 58
4.4 इंदिरा गाँधी सरकार की वापसी (Return of Indira Gandhi Government)..... 59
4.4 पंजाब में अशांति (Unrest in Punjab) 59
4.6 ऑपरेशन ब्लूस्टार (Operation Bluestar) 60
4.7 इंदिरा गाँधी की हत्या (Indira Gandhi's Assassination).. 61
4.8 इंदिरा गाँधी युग का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal of Indira Gandhi Era) 61
उपलब्धियाँ (Achievements) 61
विफलताएँ (Failures)..... 62
निष्कर्ष (Conclusion) 62

अध्याय 5

राजीव गाँधी युग (Rajiv Gandhi Era)..... 63
5.1 परिचय (Introduction)..... 63
5.2 पंजाब संकट (Punjab Crisis) 63
5.3 1984 सिख दंगे (1984 Sikh Riots)..... 64
5.4 पंजाब समझौता (Punjab Accord)..... 64
5.5 समझौते के परिणाम और पंजाब में आतंकवाद का अंत (Aftermath of the Accord and End of the Terrorism in Punjab)..... 65
5.6 असम समझौता (Assam Accord) 65
5.7 भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) 66
त्रासदी के कारण (Causes of Tragedy)..... 67
5.8 भारत का कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम (India's Computerization Program) 67
5.9 पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (Strengthening of Panchayati Raj Institutions-PRIs) . 68
5.10 जवाहर रोजगार योजना (JRY) 69
5.11 शाह बानो प्रकरण (Shah Bano Case) 69
5.12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (New Policy on Education-NPE 1986) 70
एनपीई 1986 के प्रमुख बिंदु (Key highlights of NPE 1986)..... 70
5.13 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (Operation Blackboard) 70
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की मुख्य विशेषताएँ (Salient features of Operation Blackboard) 71
5.14 बोफोर्स घोटाला (Bofors Scam)..... 71
5.14 भारतीय शांति सेना (Indian Peace Keeping Force)..... 71
5.16 राजीव गाँधी की हत्या (Rajiv Gandhi's Assassination) 72
5.17 राजीव गाँधी युग: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन (Rajiv Gandhi Era: A Critical Appraisal) 72
सकारात्मक (Positive) 73
नकारात्मक (Negative)..... 73

अध्याय 6

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार National Front Government..... 74
6.1 पूर्व 1989 गठबंधन: तीसरा मोर्चा (Pre 1989 Coalition- Third Front): 74
1989 का चुनाव (Election of 1989)..... 74
गठबंधन सरकार की शुरूआत (Beginning of Coalition Government)..... 74

6.2 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान की घटनाएँ (Events during the National Front Government) 74
6.3 मंडल आयोग (Mandal Commission) 75
मंडल आयोग रिपोर्ट की प्रस्तुति 75
सिफ़ारिशें (Recommendations) 75
तात्कालिक परिणाम (Aftermath) 75
नतीजे/निष्कर्ष (Consequences) 76
विश्लेषण (Analysis) 76

अध्याय 7

नरसिम्हा राव सरकार (Narsimha Rao Government) 78
7.1 भूमिका (Introduction) 78
7.2 आर्थिक संकट और सुधार (Economic Crisis and Reforms) 78
संकट (Crisis) 78
पूर्व शर्तें (Preconditions) 78
नई आर्थिक नीति (New Economic Policy- NEP) 79
विश्लेषण (Analysis) 79
7.3 बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid Demolition) 79
तनाव (Tension) 79
विध्वंस की ओर ले जाने वाली घटनाएँ (Events Leading to Demolition) 79
तात्कालिक परिणाम (Aftermath) 79
टाइटल सूट (स्वामित्व वाद) की वर्तमान स्थिति (Present Status of Title Suit) 79
7.4 बॉम्बे बम विस्फोट (Bombay Bomb Blasts) 80
दीर्घकालिक प्रभाव (Long Term Impact) 80
7.5 पंचायती राज (Panchayati Raj) 80
पंचायती राज अधिनियम (Panchayati Raj Act) 80

अध्याय 8

अंतर्काल वर्ष [Interregnum Years (1996-1998)] 81
8.1 बहु-दलीय काल (Multi Party Era) 81
8.2 नई आकांक्षाएँ (New Aspirations) 81
8.3 अस्थिरता (Instability) 81
8.4 गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine) 81
सिद्धांत के घटक (Principles of Doctrine) 82
औचित्य (Rationale) 82
प्रयोज्यता (Application) 82
सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of Doctrine) 82

अध्याय 9

NDA सरकार (NDA Government) 83
9.1 परिचय (Introduction) 83
9.2 पोखरण (Pokhran) 83
पोखरण-II 83
9.3 कारगिल युद्ध, 1999 (Kargil War, 1999) 84
पृष्ठभूमि (Background) 84
युद्ध का घटनाक्रम (Course of War) 85
सिलसिलेवार युद्ध (Combat in Tandem) 85
युद्ध का महत्त्व (Significance of War) 86
निष्कर्ष (Conclusion) 86
9.4 सांप्रदायिकता (Communalism) 86
भारत में सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence in India) 86
जाँच आयोग (Commission of Inquiry) 87
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच (Supreme Court Monitored Inquiry) 87

अध्याय 10

दलित आंदोलन (Dalit Movements) 88
10.1 परिचय (Introduction) 88
10.2 जाति व्यवस्था (Caste System) 88
10.3 अछूत और अस्पृश्यता (Untouchables and Untouchability) 88
10.4 स्वतंत्रता-पूर्व (Pre-Independence) 88
आदि हिंदू आंदोलन (Adi Hindu Movement) 89
गाँधी और दलित आंदोलन (Gandhi and Dalit Movement) 89
अंबेडकर और दलित आंदोलन (Ambedkar and Dalit Movement) 89
10.5 स्वातंत्र्योत्तर (स्वतंत्रता पश्चात्) विकास (Post-Independence Developments) 90
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) 90
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 [पूर्व में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के नाम से जाना जाता था] Protection of Civil Rights Act, 1955 [Formerly known as Untouchability (Offences) Act, 1955] 91
अपराधों के लिए दंड (Punishments for Offences) 91
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989] 92
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 [Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015] ... 93
10.6 अंबेडकर और दलित बौद्ध आंदोलन (Ambedkar and Dalit Buddhist Movement) 95
10.7 दलित पैंथर्स (Dalit Panthers) 95
10.8 बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) 95
10.9 दलित पूँजीवाद (Dalit Capitalism) 96
10.10 अन्य विकास (Other Developments) 96
10.11 प्रभाव और विश्लेषण (Impact and Analysis) 96

अध्याय 11

पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental Movements) 98
11.1 परिचय (Introduction) 98
11.2 ऐतिहासिक आधार (Historical Underpinnings) 98
प्राक् इतिहास (Pre-History) 98
प्रारंभ (Beginnings) 98
पश्चिमी देशों की तुलना में भारत की स्थिति (India in comparison to Western countries) 99
भारत में पर्यावरण आंदोलनों के उद्भव के कारण (Reasons for the emergence of environmental movements in India) 99
11.3 चिपको आंदोलन (Chipko Movement) 99
पृष्ठभूमि (Background) 99
विरोध (Protest) 100
माँगें (Demands) 100
सरकार की प्रतिक्रिया (Government Response) 100
महत्त्व (Significance) 100
11.4 शांत घाटी परियोजना (Silent Valley Project) 100
पृष्ठभूमि (Background) 100
विरोध (Protest) 101
सरकार की प्रतिक्रिया (Government response) 101
महत्त्व (Significance) 101
11.5 जंगल बचाओ आंदोलन (Jungle Bachao Andolan) 101
पृष्ठभूमि (Background) 101
11.6 अप्पिको आंदोलन (Appiko Movement) 101
पृष्ठभूमि (Background) 102
विरोध (Protest) 102
उद्देश्य (Objectives) 102
महत्त्व (Significance) 102
11.7 नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan) 102
पृष्ठभूमि (Background) 103
सरदार सरोवर परियोजना (Sardar Sarovar Project) 103
विरोध (Protests) 103
सरकार की प्रतिक्रिया (Government Response) 103
महत्त्व (Significance) 103
11.8 पर्यावरण एवं महिलाएँ (Environment and Women) 103
11.9 पर्यावरण संबंधी आंदोलनों का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of Environmental Movements) 105
सकारात्मक पक्ष (Positives) 105
नकारात्मक पक्ष (Negatives) 105

अध्याय 12

भूमि सुधार (Land Reforms) 106
12.1 स्वतंत्रता के समय (At the Time of Independence) 106
12.2 चरण (Phases) 106
पहला चरण (First Phase) 106
दूसरा चरण (Second Phase) 106
12.3 कुमारप्पा समिति (Kumarappa Committee) 106
12.4 जमींदारी उन्मूलन (Zamindari Abolition) 107
प्रभाव (Impact) 107
सीमाएँ (Limitations) 107
आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 107
12.5 काश्तकारी सुधार (Tenancy Reform) 108
पट्टा अवधि की सुरक्षा (Security of Tenure) 108
भूमिकर का विनियमन (Regulation of Rents) 108
स्वामित्व का अधिकार (Rights of Ownership) 108
संवैधानिक रक्षोपाय (Constitutional safeguards) 108
12.6 भूमि हदबंदी (Land Ceiling) 108
सीमाएँ (Limitations) 109
12.7 भूदान आंदोलन (Bhoodan Movement) 109
12.8 सहकारिता और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Cooperatives and Community Development Program) 110
सहकारी समितियों के प्रकार (Types of Cooperatives) 110
सहकारिताकरण की सीमाएँ (Limitations of Cooperativization) 110
सहकारी समितियों के सकारात्मक पहलू (Positives of the Cooperatives) 111
12.9 ऑपरेशन बर्गा (Operation Barga) 111
विश्लेषण (Analysis) 111
12.10 किसान आंदोलन (Farmers Movements) 112
पृष्ठभूमि (Background) 112
नव किसान आंदोलन (New Farmers' Movement) 112

अध्याय 13

महिला आंदोलन (Women's Movements) 114
13.1 परिचय (Introduction) 114
13.2 स्वतंत्रता पूर्व (Pre-Independence) 114
13.3 स्वतंत्रता पश्चात् (Post-Independence) 114
13.4 भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ (National Federation of Indian Women-NFIW) 114
13.5 स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) Self Employed Women's Association (SEWA) 115
SEWA का उद्देश्य (Aim of SEWA) 115
SEWA के लक्ष्य (Goals of SEWA) 115
13.6 मूल्य वृद्धि/महँगाई विरोधी आंदोलन (Anti-Price Rise Movement) 115
माँगें (Demands) 115
विरोध का स्वरूप (Form of Protest) 115

13.7 नव-निर्माण आंदोलन (Nav Nirman Movement) 116
कारण (Causes) 116
विरोध का स्वरूप (Form of Protest) 116
13.8 शराब विरोधी आंदोलन (Anti-liquor Movements) 116
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) 116
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) 116
आंदोलन का प्रसार (Spread of Movement) 117
सरकार की प्रतिक्रिया (Government Response) 117
13.9 आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 117

अध्याय 14

भारत का परमाणु कार्यक्रम (India's Nuclear Program) 118
14.1 उत्पत्ति (Genesis) 118
14.2 विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन (Evaluation of different Alternatives) 118
14.3 परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्भव (Emergence of Nuclear Power Program) 118
14.4 त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम (Three Stage Nuclear Power Program) 119
14.5 प्रारंभिक चरण में प्रसिद्ध नेताओं के विचार (Views of famous leaders in the initial phase) 120
जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) 120
लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) 120
14.6 वर्तमान परिदृश्य (Present Scenario) 120
14.7 भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम (India's Nuclear Weapons Program), 1944-1974 ... 120
परमाणु हथियार कार्यक्रम की उत्पत्ति के कारण (Reasons for Origin of Nuclear Weapons Program) 120
कार्यक्रम का विकास (Evolution of the Program) 120
पुनरुद्धार के कारण (Reasons for Revival) 121
ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा (Operation Smiling Buddha) 1974 121
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया (International Response) 122
परीक्षण का विश्लेषण (Analysis of Test) 122
14.8 परमाणु हथियार कार्यक्रम (Nuclear Weapons Program), 1974-98 122
1990 तक विकास (Developments till 1990) 122
भारत और अप्रसार (India and Non-Proliferation) 123
ऑपरेशन शक्ति: 1998 (Operation Shakti: 1998) 123
14.9 भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में: 1998 और उसके बाद (India as a Nuclear Power : 1998 and beyond) 124
भारतीय परमाणु नीति की मुख्य विशेषताएँ (Salient features of Indian Nuclear Policy) 124

अध्याय 15

शैक्षणिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास
(Educational, Scientific and Industrial Developments) .. 125
15.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 125
15.2 स्वतंत्रता के समय शिक्षा (Education at Independence) 126
15.3 स्वातंत्र्योत्तर (स्वतंत्रता पश्चात्) इतिहास (Post Independence Developments) 126
राधाकृष्णन आयोग, 1948-49 (Radhakrishnan Commission) 126
कोठारी शिक्षा आयोग, 1964-66 (Kothari Education Commission) 126
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 (National Policy on Education) 127
समवर्ती सूची में शिक्षा (Education in Concurrent List) 127
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy on Education – NPE) 128
प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 (Programme of Action – POA) 129
शिक्षा: एक मौलिक अधिकार (Education : A Fundamental Right) 129
नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 [New NEP (2020)] . 132
15.4 भारत में वैज्ञानिक विकास (Scientific Developments in India) 133
स्वतंत्रता-पूर्व उपलब्धियाँ (Pre-Independence Achievements) 133
स्वतंत्रता पश्चात् (After Independence) 134
15.5 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम: एक सिंहावलोकन (Indian Space Programme: An overview) 137
उत्पत्ति (Genesis) 137
प्रमुख उपलब्धियाँ (Major Milestones) 137
15.6 स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक विकास (Industrial Development before Independence) 139
15.7 स्वतंत्रता पश्चात् औद्योगिक विकास (Industrial Development after Independence) 139
औद्योगिक नीति संकल्प-1948 [Industrial Policy Resolution (IPR) - 1948] 139
आर्थिक योजना-1950 (Economic Planning-1950) ... 140
औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (Industrial Policy Resolution) 140
तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961-1966 (Third five-year plan) 140
एकाधिकार जाँच आयोग, 1964 (Monopolies Inquiry Commission) 140
वार्षिक योजनाएँ, 1966-69 (Annual Plans) 140
चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969-74 (Fourth Five-Year Plan) 140

औद्योगिक नीति विवरण, 1973
(Industrial Policy Statement)..... 141
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974-79
(Fifth Five-year Plan)..... 141
औद्योगिक नीति विवरण, 1977
(Industrial Policy Statement)..... 141
छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85
(Sixth Five-Year Plan) 141
औद्योगिक नीति विवरण, 1980
(Industrial Policy Statement)..... 141
सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90
(Seventh Five-Year Plan) 141
1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों की समीक्षा
(Review of Pre-1991 Industrial Policies) 142
15.8 उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण (LPG)
[Liberalization-Privatization-Globalization (LPG)] .. 142
पृष्ठभूमि (Background)..... 142
नवीन औद्योगिक नीति, 1991
(New Industrial Policy)..... 142
विश्लेषण (Analysis)..... 143
15.9 अन्य नीतिगत पहलें (Other Policy Initiatives)..... 143

अध्याय
1

नेहरू युग
(Nehruvian Era)

1.1 भारत का एकीकरण (Integration of India)

भारत को लंबे संघर्ष और कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। कई बार स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों पर असहमत हुए थे। उदाहरण के लिए, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्याग्रह का समर्थन किया था, जबकि अन्यों ने; जैसे- इंडियन नेशनल आर्मी (Indian National Army) ने सशस्त्र विद्रोह को प्राथमिकता दी थी, लेकिन उन सभी ने अनुभव किया, कि भारत को अपनी दुर्बल (Debilitating) और दयनीय (Pitiful) स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना आवश्यक है।

स्वतंत्रता के समय भारत कई समस्याओं; जैसे- सांप्रदायिक हिंसा, विभाजन और विस्थापित लोगों के पुनर्वास (Resettlement), विभाजन के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों और नौकरशाही का विभाजन, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, संसाधनों की कमी/समाप्ति (Deplete), राजनीतिक मोर्चे पर स्थिरता की आवश्यकता आदि का सामना कर रहा था। देशी रियासतों का एकीकरण प्रमुख मुद्दों में से एक था, जिसके बिना एकीकृत देश का सपना अधूरा रह जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में प्रमुख रूप से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र शामिल थे, जिनकी संख्या 565 थी, जो सीधे ब्रिटिश सरकार और रियासतों द्वारा प्रशासित किए जाते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता से पहले रियासतों को आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ही राज्यों पर सर्वोपरि शक्ति का उपयोग करता था।

भारतीय राज्यों का वर्गीकरण (Classification of Indian States)

स्वतंत्रता के उपरांत इन रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता/सर्वोच्चता समाप्त हो गई और ये रियासतें पाकिस्तान या भारत में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए मुक्त/स्वाधीन थीं। कई बड़ी रियासतें पूर्ण स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का सपना देखने लगीं और उसके लिए योजनाएँ बनाने लगीं। उन्होंने दावा किया कि सर्वोच्चता/संप्रभुता (Paramountcy) भारत और पाकिस्तान के नए राज्यों/देशों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

मुहम्मद अली जिन्ना ने इन रियासतों को और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 18 जून, 1947 को सार्वजनिक रूप से घोषणा की, कि "सर्वोच्चता की समाप्ति पर राज्य स्वतंत्र संप्रभु राज्य (Independent Sovereign States) होंगे और यदि वे चाहें, तो स्वतंत्र/संप्रभु रहने के लिए मुक्त/स्वाधीन हैं।"

इन सभी रियासतों को नव-स्वतंत्र भारतीय संघ में एकीकृत करना जटिल कार्य था। हालाँकि, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में अनुनयन (Persuasion) और दबाव (Pressure), दोनों का उपयोग करके अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत कर लिया गया था, लेकिन तीन रियासतें, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर ने एकीकरण में सहयोग नहीं किया जिससे समस्या बनी रही।

भारत के राजनीतिक संगठन को सरल बनाने के अलावा, रियासतों के क्षेत्रीय एकीकरण से इकाइयों में एकरूपता, सरलता और व्यवहार्यता (Viability) आई। इस प्रकार, जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, तो संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों की निम्नलिखित चार श्रेणियाँ शामिल की गई थीं:

भाग-A राज्य (Part-A States)

ब्रिटिश भारत के पूर्व प्रांत, जो निर्वाचित/मनोनीत गवर्नर और राज्य विधायिका द्वारा प्रशासित थे।

216 रियासतों का ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विलय कर दिया गया, जिनकी जनसंख्या 19 मिलियन थी और उन्हें भाग-A राज्यों के रूप में नामित/वर्गीकृत किया गया। इनमें शामिल हैं: (1) असम, (2) बिहार, (3) बॉम्बे, (4) मध्य प्रदेश, (5) मद्रास, (6) उड़ीसा, (7) पंजाब, (8) उत्तर प्रदेश, (9) पश्चिम बंगाल।

भाग-B राज्य (Part-B States)

पूर्व रियासतें

275 रियासतों को नई व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने के लिए एकीकृत किया गया, जिनकी जनसंख्या लगभग 35 मिलियन थी और उन्हें भाग-B राज्यों के रूप में नामित/वर्गीकृत किया

गया। इनमें शामिल हैं: (1) हैदराबाद, (2) जम्मू और कश्मीर, (3) मध्य भारत, (4) मैसूर, (5) पेप्सू (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य-संघ), (6) राजस्थान, (7) सौराष्ट्र, (8) त्रावण ाकोर-कोचीन।

भाग-C राज्य (Part-C States)

पूर्व मुख्य आयुक्त के द्वारा प्रशासित प्रांत और कुछ रियासतें।

अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण 61 रियासतें, जो उपर्युक्त उल्लिखित दोनों श्रेणियों में शामिल नहीं थीं, उन्हें केंद्र-शासित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया और भाग-C राज्य कहा गया। इस श्रेणी में शामिल हैं: (1) अजमेर, (2) बिलासपुर, (3) भोपाल, (4) कुर्ग, (5) दिल्ली, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) कच्छ, (8) मणिपुर, (9) त्रिपुरा और (10) विंध्य प्रदेश।

भाग-D राज्य (Part-D States)

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेट-गवर्नर द्वारा प्रशासित।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को भाग-D राज्य नामक एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

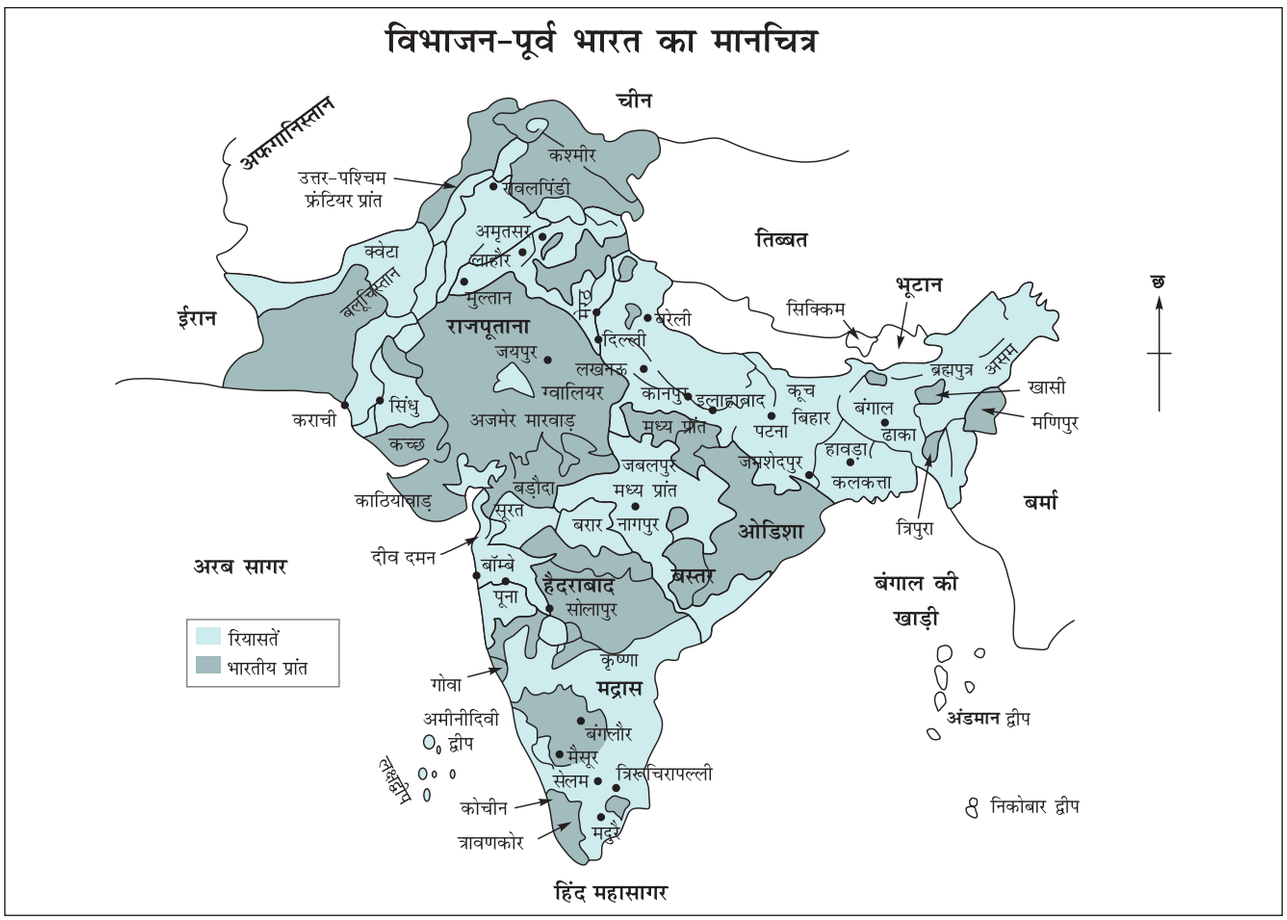

रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States)

ब्रिटिश भारत के साथ रियासतों का संबंध, उनके एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न संधियों पर आधारित था। जिससे ब्रिटिश क्राउन का विदेशी, अंतर-राष्ट्रिय/अंतर्राज्यीय संबंधों (Inter-state relations) और रक्षा पर अलग-अलग स्तर का नियंत्रण था। इन संबंधों का विकास एक शताब्दी के दौरान हुआ था।

देशी रियासतों के शासकों ने भारत में ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा इन रियासतों का प्रतिनिधित्व इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) और चैंबर ऑफ प्रिंसेस (Chamber of Princes) में किया गया था। इस प्रकार, राजकुमारों/रियासतों ने ब्रिटिश क्राउन के साथ प्रभाव/प्रभुत्व का एक माध्यम बनाए रखा।

स्वतंत्रता के पश्चात् यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उभरा कि ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित करने वाले नए देश या राज्यों की प्रकृति और आकार किस प्रकार का होगा। पाकिस्तान निर्माण के लिए विभाजन की माँग एक केंद्रीय मुद्दा था, हालाँकि यह एकमात्र मुद्दा नहीं था। विभाजन योजना (Partition Plan) रियासतों के भविष्य से संबंधित नहीं थी, क्योंकि यह योजना केवल प्रांतों तक ही सीमित थी।

हालाँकि, तकनीकी रूप से रियासतों के शासक किसी भी डोमिनियन (भारत या पाकिस्तान) में शामिल होने के लिए मुक्त/स्वाधीन थे, लेकिन कुछ भौगोलिक कारण थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लगभग 565 रियासतों में से अधिकतर भौगोलिक रूप से भारतीय डोमिनियन के साथ जुड़ी थीं। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना के लिए सहमत होने के उपरांत भी, नए भारतीय राज्य का राजनीतिक भूगोल/भू-भाग अस्पष्ट बना हुआ था। स्वतंत्रता से पहले व्यापार, वाणिज्य और संचार के विकास ने जटिल समझौतों के माध्यम से रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ संबद्ध कर दिया था। रियासतों के एकीकरण के बगैर स्वतंत्रता के उपरांत, रेलवे, सीमा-शुल्क, सिंचाई, बंदरगाहों के उपयोग आदि से संबंधित समझौते समाप्त/जटिल हो जाते, जिससे एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती। साथ ही इन रियासतों के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उन्होंने भी भारत के साथ एकीकृत होने की इच्छा जताई थी।

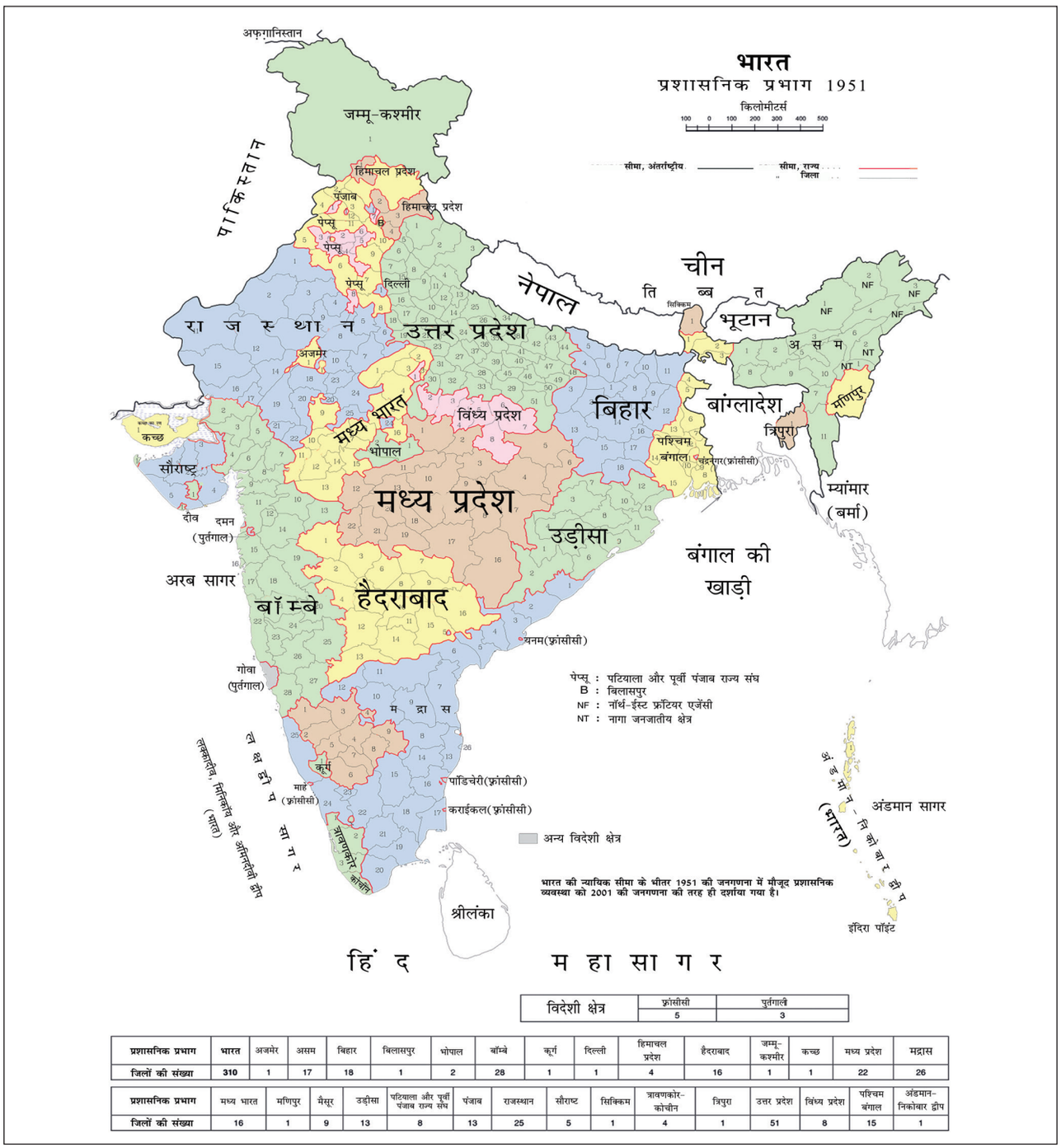

विदेशी क्षेत्र	फ्रांसीसी	पुर्तगाली
	5	3

प्रशासनिक प्रभाग	भारत	अजमेर	असम	बिहार	बिलासपुर	भोपाल	बॉम्बे	कूर्ग	दिल्ली	हिमाचल प्रदेश	हैदराबाद	जम्मू-कश्मीर	कच्छ	मध्य प्रदेश	मद्रास
जिलों की संख्या	310	1	17	18	1	2	28	1	1	4	16	1	1	22	26

प्रशासनिक प्रभाग	मध्य भारत	मणिपुर	मैसूर	उड़ीसा	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ	पंजाब	राजस्थान	सौराष्ट	सिक्किम	त्रावणकोर-कोचीन	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	विंध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल	अंडमान-निकोबार द्वीप
जिलों की संख्या	16	1	9	13	8	13	25	5	1	4	1	51	8	15	1

गई, जबकि कश्मीर की सीमाओं से दुश्मनों को दूर भगाने का पूरा नियंत्रण सेना के हाथ में था। अब संघर्ष विराम रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा बन गई है, जिससे पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद जारी है।

भारत-चीन सीमा विवाद (Indo-China Border Dispute): तिब्बत पर पंचशील समझौते के दौरान दूरदर्शिता की कमी दिखाने के लिए भी नेहरू की आलोचना की जाती है, जब उन्होंने स्वेच्छा से तिब्बत पर चीन के दावे को मान्यता दी थी। उस समय तिब्बत पर चीन के दावे को मान्यता देने के बदले, चीन को नेफा (NEFA) को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने के लिए पारस्परिकता का उपयोग किया जा सकता था। इससे चीन के साथ सीमा विवाद सुलझ जाता।

कृषि को कम महत्त्व (Ignorance of Agriculture): विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में भारी उद्योगों के विकास पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण, जिसमें महालनोबिस योजना भी शामिल है, कृषि क्षेत्र की अनदेखी हुई और जल्द ही भारत को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा और उसे अन्य देशों से खाद्य सहायता माँगनी पड़ी।

बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy): हालाँकि इसका उद्देश्य आत्म-निर्भरता का निर्माण करना था। बंद अर्थव्यवस्था प्रणाली के कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, जो अंततः 1991 के संकट में परिणत हुआ, जब भारत को BOP संकट का सामना करना पड़ा।

1.6 निष्कर्ष (Conclusion)

यह समझा जाना चाहिए कि यह इस अवधि के दौरान प्रदान की गई स्थिरता ही थी, जिसने भारत को उस रास्ते पर जाने से काफी हद तक रोका है, जिस पर उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान चला गया था। यह वह अवधि थी, जिसने लोकतंत्र को जड़ें जमाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। यह नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर आदि जैसे नेताओं का भी दृष्टिकोण था कि भारत बहुत जटिल मुद्दों का सामना करने के बाद भी एकजुट है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।

■■■■

? विगत वर्षों की मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों को हल कीजिए

1. उन्नीसवीं सदी के मध्य से राज्यों और क्षेत्रों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। **(2022)**
2. भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों और सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का मूल्यांकन कीजिए। **(2021)**
3. चर्चा कीजिए कि क्या हाल ही के दिनों में नए राज्यों का गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है या नहीं? **(2018)**
4. क्या भाषायी राज्यों के गठन से भारतीय एकता का उद्देश्य मज़बूत हुआ है? **(2016)**

अध्याय
2

लाल बहादुर शास्त्री युग
(Lal Bahadur Shastri Era)

2.1 परिचय (Introduction)

1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री पद को लेकर प्रश्न उठा। प्रधानमंत्री पद के लिए दो प्रमुख दावेदार मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री थे। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के एक समूह, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद ग्रहण करेंगे। अत: उन्होंने जून, 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

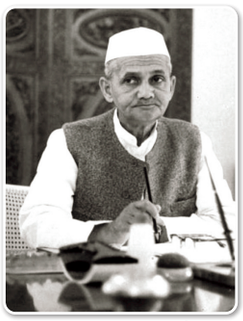
लाल बहादुर शास्त्री

चुनौतियाँ (Challenges)

जब लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उनके समक्ष कई चुनौतियाँ थीं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- स्थिर/अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था, असंतुलित भुगतान संतुलन और खाद्यान्न की भारी कमी।
- 1950 में संविधान द्वारा प्रदत्त पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखने के लिए तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन।
- अलग राज्यों (पंजाब की तरह) और गोवा के महाराष्ट्र में विलय की माँग।
- नागालैंड में स्वतंत्रता की माँग और उससे जुड़ा ग्रेटर नागालैंड विद्रोह।
- कश्मीर मुद्दा और कश्मीर में पाकिस्तान की कूटनीति।
- अक्टूबर, 1964 में परमाणु परीक्षण से चीन की शक्ति में वृद्धि।

प्रतिक्रिया (Response)

- हरित क्रांति की शुरुआत के परिणामस्वरूप खाद्यान्न का अत्याधिक उत्पादन कर खाद्य संकट की समस्या का समाधान किया गया। निम्नलिखित चर्चाओं में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है।
- प्रधानमंत्री शास्त्री ने गैर-हिंदी भाषी राज्यों को आश्वासन दिया कि उनकी क्षेत्रीय भाषा में अपना कार्य करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। यद्यपि वह इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने में विफल रहे, क्योंकि उन्हें हिंदी समर्थक और हिंदी विरोधी समूहों के विचारों में एकरूपता/साम्यता नहीं प्राप्त हो सकी।
- पंजाब में अलग राज्य की माँग को भी शास्त्री जी के द्वारा निर्णायक तरीके से नहीं निपटाया जा सका और इस मामले को उनकी उत्तराधिकारी इंदिरा गाँधी द्वारा हल करने के लिए छोड़ दिया गया।
- यद्यपि नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 में किया गया था, लेकिन उग्रवाद में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में अशांति फैल गई। शास्त्री जी के कार्यकाल में राज्य में विद्रोह का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका।
- लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में ही कश्मीर का मुद्दा उग्र होने लगा था। कश्मीर घाटी में अशांति का फायदा पाकिस्तान ने उठाया, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसका निम्नलिखित चर्चाओं में अलग से वर्णन किया गया है।
- जैसे ही चीन ने परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तभी व्यक्तिगत रूप से सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण के पक्ष में रहने वाले तात्कालिक परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक डॉ. होमी जे. भाभा ने कहा कि भारत संभाव्य स्थितियों में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन शास्त्री जी, डॉ. भाभा के इस मत के पक्ष में नहीं थे।

2.2 राजनीतिक विकास (Political Developments)

कामराज योजना (Kamaraj Plan)

1962 में चीन के विरुद्ध युद्ध में हार के बाद न सिर्फ सरकार, बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी छवि खराब हो गई। इसके अलावा सत्ता में पंद्रह वर्षों के शासनकाल ने पार्टी को आत्मसंतुष्ट बना दिया।

ऐसे संकेत थे कि इसका ज़मीनी वास्तविकता से संपर्क टूट गया है। यह उप-चुनावों में हार और DMK जैसी क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत से स्पष्ट था।

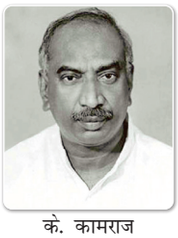
के. कामराज

मद्रास के मुख्यमंत्री के. कामराज ने DMK से खतरा महसूस किया। DMK के उत्थान को रोकने और कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने 'कामराज योजना' नामक एक उपाय की सिफारिश की। इसके तहत उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपना मंत्री पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी के पुनर्निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इस बात पर अमल करने के लिए उन्होंने अक्टूबर, 1963 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। छह केंद्रीय मंत्री और छह मुख्यमंत्री, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, बीजू पटनायक और एस.के. पाटिल शामिल थे, ने भी ऐसा ही किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

कुमारस्वामी कामराज (Kumaraswamy Kamaraj)

कुमारस्वामी कामराज (1903-1975) नादर/नदार जाति से संबंधित थे, जो हिंदुओं में सबसे दलित जातियों में से एक थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के एक प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निधन से लेकर 1969 में कांग्रेस के विभाजन तक भारत की नियति को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई और भारत के दो महान प्रधानमंत्रियों, यानी लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गाँधी के उदय के पीछे उनकी भूमिका के कारण उन्हें 'किंग मेकर' के रूप में जाना जाता है। वह 1937 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। बाद में वह 1946 में फिर से इसके लिए चुने गए। वह 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए भी चुने गए और बाद में 1952 में संसद के लिए भी चुने गए।

वह 1954 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने और 1963 तक लगातार तीन कार्यकाल तक सेवा की। कांग्रेस के उत्साह में गिरावट का एहसास होने पर उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी ऐसा करने को कहा। पद से इस्तीफा देने के बाद, वह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए और 4 वर्षों (1964-1967) तक इसके अध्यक्ष रहे।

क्षेत्रीय दलों का उदय (Rise of Regional Parties)

भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जिसमें लोगों की आकांक्षाएँ अलग-अलग हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ।

तमिलनाडु में DMK (DMK in Tamil Nadu)

इसका गठन 1949 में अन्नादुरई द्वारा किया गया। यह शुरू में एक ब्राह्मण विरोधी, उत्तर-भारत विरोधी और हिंदी विरोधी पार्टी थी। यह दक्षिणी राज्यों, यानी द्रविड़नाडु के एक स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य की माँग करती थी। लेकिन यह महसूस करने के बाद कि अलग राष्ट्र-राज्य की उसकी माँग पूरी नहीं हो सकती और एकता के दायरे में ही तमिल संस्कृति की रक्षा संभव है, उसने अपनी माँगें राज्य तक सीमित कर दीं। उन्होंने अपने ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन को भी कम महत्त्व दिया, क्योंकि इससे ब्राह्मणों का पलायन हुआ, जिससे तमिलनाडु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर असर पड़ा। उन्होंने चुनावों में भाग लेना शुरू किया और 1967 में तमिलनाडु में सरकार बनाई, जिसमें अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने।

महाराष्ट्र में शिवसेना (Shivsena in Maharashtra)

इसका गठन 1966 में बाल ठाकरे द्वारा 'बॉम्बे महाराष्ट्र वालों के लिए' ('Bombay for Maharashtrians') के एजेंडे के साथ किया गया था। इसने भूमिपुत्रों के लिए नौकरियों जैसी माँगों के साथ क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने की माँग की। इसी प्रकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं की रक्षा के लिए देश के अन्य हिस्सों में भी विभिन्न क्षेत्रीय दलों का गठन किया गया। उदाहरण के लिए 1980 के दशक की शुरुआत में तेलुगु देशम पार्टी का गठन हुआ, 1985 में असम में असम गण परिषद् का गठन हुआ आदि।

क्षेत्रीय दलों के उदय का प्रभाव (Impact of Rise of Regional Parties)

- क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय हित की आवाज़ उठाई, जिससे भारतीय संघ मजबूत हुआ।
- उन्होंने केंद्र में गठबंधन सरकारों के गठन में भूमिका निभाई।
- उनके उदय से लोकसभा में क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा।
- अक्सर, क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। इससे उप-राष्ट्रीय भावनाएँ जागृत हुईं, जिससे विभिन्न अवसरों पर कानून और व्यवस्था की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।